जोधपुर, 24 अगस्त।

शहर में घर–घर कचरा संग्रहण की योजना में दो बाद विफल हो चुके नगरनिगम ने एक बार फिर इसके लिए जमीनी स्तर पर कवायद शुरू की है और इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श करने को लेकर गुरूवार को महापौर घनश्याम ओझा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि नगरनिगम की ओर से पूर्व में भी दो बाद डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की शुरूआत की गई थी लेकिन विभिन्न खामियों के चलते वह प्लानिंग सफल नही हो सकी इसी के चलते इस बार इस योजना को फुलप्रुफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में महापौर ओझा ने प्रस्ताव रखा कि इस बार पूरे शहर का ठेका एक ही कंपनी को देने की बजाय छोटे छोटे स्तर पर ठेके दिए और यदि संभव हो सके तो वार्डवार इसकी जिम्मेदारी दी जाए जिससे इस योजना की उचित तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस योजना को शुरू करने मे मौहल्ला विकास समितियों और स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाए और यदि वह इस कार्य की जिम्मेदारी लेतें है तो उन्हे प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य सौंपा जाए वही यदि मौहल्ला विकास समिति या कोई स्वंयसेवी संस्था इसके लिए तैयार नही होती है वहां जिनके पास स्वंय की लोडिंग टैक्सी है उन्हे यह काम सौंपा जाए जो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कचरा संग्रहण का कार्य करे जिसके लिए निगम उनको एक निर्धारित राशि देगा और उसके बाद वह अपना स्वंय का रोजगार कर सकेगा। बैठक मे इसके लिए शहर के गणमान्य नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और मौहल्ला विकास समितियो ंके सुझाव भी लिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में निगम आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा, सीवरेज समिति अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सोलंकी, सफाई समिति अध्यक्ष भंवरकंवर, प्रतिपक्ष नेता गणपतसिंह, एक्सईएन सम्पत मेघवाल सहित समस्त मुख्य सफाई निरीक्षक उपस्थित थे।

पहले तीन महीनें नही लेगें कोई शुल्क

निगम आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा ने बताया कि बैठक मे तय किया गया कि पिछले अनुभव से सीख लेते हुए इस बार निगम इस योजना के शुरूवाती तीन महीने तक आमजन से कोई शुल्क नही वसूल करेगा और यह सेवा निःशुल्क रहेगी। आयुक्त कसेरा ने बताया कि इन तीन महीनों से देखा जाएगा कि किस मौहल्ले से कितना कचरा आ रहा है, कितनी सफाई हो रही है, मौहल्लेवासी किस तरह का सहयोग कर रही है। इन तीन महीनो ंकी सेवाओ ंके बाद जब मौहल्लेवासी इस सेवा से संतुष्ट होगें तो फिर उसके बाद उनसे शुल्क लिया जाएगा। कसेरा ने बताया कि 100 वर्ग गज तक के मकानों से महज 40 रूपए और 100 वर्ग गज से 300 वर्ग गज तक के मकानो ंसे 80 रूपए मासिक शुल्क लिया जाएगा।

फुलप्रुफ प्लान होगा तैयार

महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि बैठक मे तय किया गया कि इस बार इस योजना को शुरू करने से पहले जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी की जाए। इसके लिए पहले यह तय किया जाए कि किस वार्ड में कितनी टैक्सी की आवश्कता होगी और उनका रूट चार्ट क्या रहेगा। यह तय होने के बाद टैंडर आदि की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

फोटोः– डोर टू डोर कचरा संगहण योजना की तैयारी को लेकर चर्चा करते महापौर एवं निगम अधिकारीगण।

जोधपुर, 24 अगस्त।

नगरनिगम रोशनी शाखा की ओर से बार बार एलईडी लाईट्स के संबंध में सूचनाएं मांगें जाने के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध नही कराए जाने को महापौर घनश्याम ओझा ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए है। महापौर घनश्याम ओझा ने एक यूओ नोट जारी कर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि निगम की रोशनी शाखा से एलईडी लाईट्स के संबंध मे बार बार सूचनाएं मांगी जा रही है। ओझा ने बताया कि सूचनाएं समय पर नही देने से सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील का भी निस्तारण काफी धीमी गति से हो रहा है और प्रथम अपील का निस्तारण समय पर नही होने से राज्य स्तर पर द्वितीय अपील का निर्णय निगम के विरूद्व हो जाता है जो कि काफी गंभीर है। महापौर ओझा ने यूओ नोट में निर्देश दिए कि एलईडी लाईटों की सूचना उपलब्ध नही करवाने के लिए संबंधित कार्मिक एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का निस्तारण समय पर नही करने वाले कार्मिकों का वेतन तक तक रोका जाए जब तक उनकी ओर से एलईडी लाईट की सूचना ओर प्रथम अपील संबंधी कार्य को पूरा नही कर दिया जाता है।